राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार , 02 मई 2026
वर्ष 14, अंक 23, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

प्रीपेड मीटर : बैलेंस खत्म होने पर तुरंत नहीं कटेगी बिजली...03

मां, माटी और मानुष की सरकार बना रहे हैं...04

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का शिलान्यास और उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज लद्दाख के लेह में केन्द्रशासित प्रदेश के लिए विभिन्न डेयरी अवसंरचना एवं सहकारी पहलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल एवं जॉर्ज कुरियन तथा लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए सहकारिता मॉडल के तहत आज लद्दाख में ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज करगिल जैसी ऊंची जगह पर 10 टीएलपीडी क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास हुआ है, जिसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करने की है। करगिल की महिलाएं डेयरी प्लांट के माध्यम से अपने जीवन में उजाला ला सकती हैं, परिवार की मदद कर सकती हैं और आत्मनिर्भर भी बना सकती हैं। श्री शाह ने कहा कि वे एक ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां की महिलाओं ने ऐसी ही छोटी-छोटी डेयरियों के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इतनी संभावना है कि यहां की महिलाएं अपने परिवार और बच्चों की अच्छी पढ़ाई-लिखाई में योगदान कर सकें। शाह ने कहा कि 25 करोड़ की लागत से जिस नई परियोजना की शुरुआत होने जा रही है, वह निश्चित रूप से करगिल की माताओं-बहनों के लिए शुभंकर साबित होगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि लेह में पहले से काम कर रहे मिल्क प्लांट में प्रतिदिन उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि लद्दाख में आईटीबीपी और सेना बहुत बड़े खरीददार हैं। यहां सीमा पर 18,000 जवान रहते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आईटीबीपी और सेना की दूध, दही और पनीर की जरूरत इस प्लांट से पूरी होगी। शाह ने कहा कि 45 लाख रुपए की लागत से एक मोबाइल प्रयोगशाला भी लॉन्च की गई है, जिससे दूध की क्वालिटी के रखरखाव में बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि एंड्रॉइड आधारित-ऱ्स्ट्स ऐप का शुभारंभ भी हुआ है, जिससे हमारे दुग्ध उत्पादक पशुपालक पारदर्शिता के साथ अपने दूध का हिसाब-किताब एक ही ऐप पर देख पाएंगे। इससे दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के मन में आत्मविश्वास भी जागृत होगा। उन्होंने कहा कि आज जिन पाँच पशुपालकों को पुरस्कृत किया गया वे करगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप हैं। अमित शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी ने एक समझौता किया है। इससे लद्दाख को देश के बाजार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि लद्दाख के ऑर्गेनिक उत्पादों को दिल्ली का बड़ा बाजार मिलना चाहिए। श्री शाह ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से आग्रह किया कि वह इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड को साथ लेकर एक त्रिपक्षीय एमओयू करें। उन्होंने कहा कि मदर डेयरी के प्रोडक्ट तो यहां बेचे ही जाएं, साथ ही मदर डेयरी अन्य सहकारी संस्थाओं के माध्यम से यहां के प्रोडक्ट की भी देश भर में मार्केटिंग की व्यवस्था करे। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम लद्दाख में डेयरी अवसंरचना का विस्तार करने जा रहे हैं। लेह में आने वाले दिनों में 70 करोड़ रुपए की लागत से 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वह लेह में बढ़ने वाली संभावनाओं का तो दोहन करेगा ही, साथ ही करगिल में लगाए जा रहे संयंत्र से दूध बढ़ने पर दोनों क्षेत्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहां के मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गाय और भैंस उपलब्ध कराने का काम होगा। लगभग हर साल अच्छी नस्ल की 500 गाय और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख काफी ठंडा प्रदेश है, यहां ऑक्सीजन की भी कमी होती है। इसलिए रिसर्च करके यहाँ के मौसम में ढल सकने वाले पशु स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि आगामी 10 साल में पशुओं की संख्या में लगभग तीन गुनी बढ़ोतरी करने की योजना है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस योजना को लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। शाह ने कहा कि लद्दाख मिल्क फेडरेशन और एनडीडीबी में समझौता होने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दुग्ध उत्पादक इससे जुड़े हैं। उन्होंने एनडीडीबी के अध्यक्ष से कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में, जहां पशुपालन संभव हो, वहां एनडीडीबी की पहुँच होनी चाहिए और उन्हें इन सभी पशुपालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां दैनिक दूध की खरीद लगभग 7000 किलोलीटर तक पहुंची है। इसे अगले चार साल में 21,000 किलोलीटर तक पहुंचाकर यहां के किसानों की समृद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज एक डेयरी प्लांट का उन्नयन और पुनरुद्धार भी किया गया। पांच टीएलडीपी से बढ़ाकर इसकी क्षमता 10 टीएलडीपी कर दी गई साथ ही सेना के साथ एमओयू से इसे निश्चित रूप से फायदा होगा।

योगी सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ को और धार देगा ‘संध्या संवाद ‘

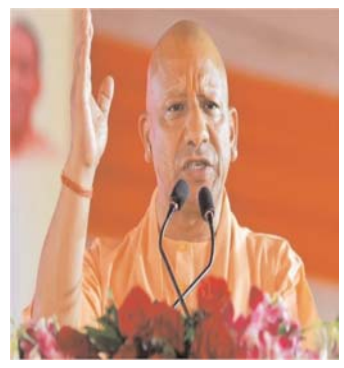

योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से देवीपाटन मंडल में ग्राम पंचायत स्तर पर ‘संध्या संवाद कार्यक्रम’ की अभिनव पहल की जा रही है। इसकी शुरुआत 8 मई को श्रावस्ती की एक ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस दौरान ग्राम पंचायत में ‘संध्या संवाद कार्यक्रम’ के तहत देवीपाटन मंडलायुक्त द्वारा ग्रामीणों के साथ खुली चौपाल में उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा समस्या का तत्काल समाधान किया जाएगा। इसके अलावा योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ देने के लिए मंडलायुक्त के निर्देश पर ग्राम पंचायत में शिविर भी लगाया जाएगा, जहां तत्काल योजनाओं को लाभ दिया जाएगा।

‘संध्या संवाद कार्यक्रम’ में ग्रामीणों से स्थापित किया जाएगा सीधा संवाद

देवीपाटन मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मंत्र को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ‘संध्या संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा प्रयास रहा है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए प्रदेश में समय-समय पर विभिन्न जनसंपर्क और जनसुनवाई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसे में सीएम योगी की मंशा के अनुरूप देवीपाटन मंडल के चार जिलों गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में ग्राम पंचायत स्तर पर ‘संध्या संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 8 मई को श्रावस्ती में चयनित ग्राम पंचायत स्तर पर मंडलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अगुवाई में ‘संध्या संवाद कार्यक्रम’ के तहत खुली चौपाल आयोजित की जाएगी। संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण अपनी समस्याएं, सुझाव और अनुभव सीधे प्रशासन के सामने रख सकेंगे। इससे न केवल समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की भी पहचान की जा सकेगी।

एक दिवसीय विशेष शिविर में सरकारी योजनाओं का मौके पर ही दिया जाएगा लाभ

मंडलायुक्त ने बताया कि चयनित ग्राम में एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा, जहां पात्र व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को उसी दिन प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजनाओं का पारदर्शी तरीके से वितरण किया जाए। इसके अलावा श्रावस्ती में 8 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनसुनवाई की जाएगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और पेंशनरों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की विभागीय और पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जिले में निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इस दौरान मंडलायुक्त द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गये हैं ताकि कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। वहीं, शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच श्रावस्ती की चयनित ग्राम पंचायत में ‘संध्या संवाद’ का आयोजन किया जाएगा।

संक्षिप्त ख़बरें

लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की मौत से सनसनी: 11वीं मंजिल से गिरा युवक, दर्दनाक हादसे में चली गई जान, वजह खंगालने में जुटी पुलिस

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में एक आवासीय इमारत की 11वीं मंजिल से गिरकर 31 वर्षीय एक प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, घटना बृहस्पतिवार रात करीब 8:45 बजे कुर्सी रोड स्थित जनेश्वर एन्क्लेव में हुई। एक व्यक्ति के 11वीं मंजिल से गिरने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को जमीन पर गंभीर रूप से घायल पाया। पुलिस ने बताया कि घायल व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस से सरकारी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। निरीक्षण और साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक फोरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। बयान में कहा गया है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की पत्नी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, उस व्यक्ति की पहचान प्रबल जैन के रूप में की गई, जो सीतापुर जिले के महमूदाबाद का निवासी था। वह अपनी पत्नी के साथ जनेश्वर एन्क्लेव के डी-ब्लॉक के एक फ्लैट में किराए के मकान में रह रहा था। प्रारंभिक जांच और पत्नी से मिली जानकारी से पता चलता है कि जैन ने कथित तौर पर 11वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कहा कि वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी यहां एक प्रीमियम शॉपिंग मॉल में फ्लोर मैनेजर के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने कहा कि दंपत्ति की शादी को लगभग एक साल हो गया था और मृतक के परिवार के सदस्य घटनास्थल पर मौजूद हैं। बयान में कहा गया है कि आगे की जांच चल रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नेपाल के युवा PM बालेन शाह का पहला विदेश दौरा: PM Modi का न्योता स्वीकार, मई में आ सकते हैं भारत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नेपाल के नवनियुक्त और सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह (बालेन) अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए भारत आ सकते हैं। काठमांडू में सरकार ने इस ऐतिहासिक दौरे का होमवर्क शुरू कर दिया है। यह यात्रा न केवल कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह बालेन सरकार की पड़ोसी पहले की प्राथमिकता को भी दर्शाती है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरे को अंतिम रूप देने के लिए तीन चरणों में बातचीत होगी। मई के दूसरे हफ्ते में काठमांडू में दोनों देशों के विदेश सचिवों की मुलाकात होगी। इसके तुरंत बाद नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों के बीच एजेंडा फाइनल किया जाएगा। इन बैठकों के बाद ही प्रधानमंत्री बालेन शाह की यात्रा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान होगा।

PM Modi का न्योता और जयशंकर से मुलाकात

नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने पुष्टि की है कि बालेन शाह ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। करीब तीन हफ्ते पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ हुई मुलाकात में इस दौरे की नींव रखी गई थी। खनाल ने यह भी कहा कि भारत-नेपाल के बीच लगभग 40 द्विपक्षीय तंत्र (Mechanisms) हैं जिनमें से कई फिलहाल निष्क्रिय हैं, इस यात्रा से उन्हें पुनर्जीवित करने की उम्मीद है। नेपाल की राजनीति में यह परंपरा रही है कि नए प्रधानमंत्री अपना पहला विदेश दौरा भारत से शुरू करते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इसमें अपवाद भी देखे गए। बता दें कि 2008 में तत्कालीन पीएम पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’ ने परंपरा तोड़ते हुए पहली यात्रा बीजिंग (चीन) की थी। वहीं 2024 में केपी शर्मा ओली ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए थाईलैंड को चुना था। जिसके बाद 2026 में अब 35 वर्षीय बालेन शाह फिर से भारत को प्राथमिकता देकर रिश्तों में नई गर्माहट लाने का संकेत दे रहे हैं।

बालेन शाह: रैपर से प्रधानमंत्री तक का सफर

काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन शाह ने मार्च 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (ऱ्स्क) की भारी जीत के बाद नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख और प्रशासनिक सुधारों ने उन्हें युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है।

LPG ब्लैक मार्केटिंग पर कानूनी शिकंजा, कोर्ट ने लगाया 28 लाख रुपये का जुर्माना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और ज्यादा कीमत पर बेचने से जुड़े एक मामले को गंभीरता से लेते हुए, CBI कोर्ट ने हाल ही में दोषियों पर 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और पार्टनर्स को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है. CBI ने 2010 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत केस दर्ज किया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) नीतू नागर ने वनिता घोष और कपिल गुप्ता को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत जुर्म के लिए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई और हर एक पर 70 हजार रुपये का जुर्माना और फर्म सिवानिक्का एंटरप्राइज पर उसके पार्टनर्स घोष और गुप्ता के जरिए 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने दोषियों को 25,77,508 रुपये का गलत फायदा और सरकारी खजाने को गलत नुकसान पहुंचाने के लिए 26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की सारी रकम जमा कर दी गई है. दोषियों को सजा देते समय, कोर्ट ने कई बातों पर ध्यान दिया, जैसे ट्रायल का लंबा समय, दोषियों का पछतावा और उनकी उम्र.

कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

कोर्ट ने 22 अप्रैल को दिए गए सज़ा के आदेश में कहा कि उनकी उम्र और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोषी 2011 से इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे हैं, दोषियों, यानी वनिता घोष, कपिल गुप्ता और दोषी मेसर्स शिवनिक्का एंटरप्राइजेज, अपने पार्टनर वनिता घोष और कपिल गुप्ता के ज़रिए एसेंशियल कमोडिटीजएक्ट, 1955 के सेक्शन 3 के साथ 7 और 9 के तहत सज़ा के लायक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है. उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, 1955 के सेक्शन 3, 7 और 9 के साथ पढ़े जाने वाले जुर्म के लिए सजा दी गई है. दोषियों, वनिता घोष और कपिल गुप्ता को ऱ्स्ट से गुजरना होगा और हर एक को 70 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा और दोषी मेसर्स शिवनिक्का एंटरप्राइजेज, अपने पार्टनर वनिता घोष और कपिल गुप्ता के जरिए 60 हजार रुपये का जुर्माना देगी. CBI ने कहा था कि दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए, ताकि समाज में एक रोकने वाला मैसेज जाए, और एक जैसी सोच वाले लोग क्रिमिनल और घिनौने कामों में शामिल होने से हतोत्साहित हों.

दोषियों को सजा देते हुए रखा इन बातों का ख्याल

CBI ने कहा था कि दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए, ताकि समाज में एक रोकने वाला मैसेज जाए, और एक जैसी सोच वाले लोग क्रिमिनल और घिनौने कामों में शामिल होने से बचें. कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाते समय कम करने वाले फैक्टर्स पर विचार करने के बाद नरम रुख अपनाया और कहा, ‘दोषियों वनिता घोष और कपिल गुप्ता द्वारा बताए गए कम करने वाले हालात को देखते हुए, अगर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जेल की सजा दी जाती है, तो वह सख्त होगी. ‘ सजा सुनाते हुए इन बातों का रखा ध्यान कोर्ट ने कहा कि सजा सुनाना एक नाजुक काम है जिसमें कोर्ट को मामले के सभी फैक्ट्स और हालात पर ध्यान देना होता है और कोर्ट इस बात से अनजान नहीं रह सकता कि सज़ा का मकसद बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करना होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने पछतावे की सच्ची इच्छा दिखाई है, इसलिए, उन्हें सुधार का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, ताकि वे देश के काम के नागरिक बन सकें, छ्ठ्रूनागर ने कहा, ‘साथ ही, दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे समाज के दूसरे समान सोच वाले लोग जुर्म की दुनिया में आने से हतोत्साहित हों. हालांकि, दोषियों को सजा सुनाते समय एक अच्छा बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है. ‘

कौन से एक्ट में दी सजा?

कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के सेक्शन 3 के साथ सेक्शन 7 और 9 के तहत सजा वाले जुर्म के लिए चार्ज तय किए थे. आरोपियों ने बोलकर कहा कि वे अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं और किसी ने भी उन्हें अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया है.

क्या बोले दोषियों के वकील?

वनिता घोष के वकील निशांक मट्टू ने दलील दी कि वह शादीशुदा हैं और उनके चार बच्चे हैं. उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है, इसलिए उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. वह 62 साल की हैं और बुढ़ापे से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रही हैं. उन्हें ब्रेन हैमरेज भी हुआ है और अभी उनका कई बीमारियों का इलाज चल रहा है. कपिल गुप्ता के वकील ने कहा कि वह शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे हैं. वह अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं. उनकी 63 साल की पत्नी और 30 और 28 साल के दो बेटों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है. वह डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बुढ़ापे से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने प्रार्थना की कि उनके खिलाफ नरम रवैया अपनाया जाए.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि यह मामला CBI, ACB, नई दिल्ली में 20 अगस्त, 2010 को मेसर्स के खिलाफ रजिस्टर किया गया था. शिवनिक्का एंटरप्राइजेज, वनिता घोष, उसके पार्टनर और दूसरे अनजान सरकारी कर्मचारियों/प्राइवेट लोगों पर, गैर-कानूनी लोगों को बहुत ज्यादा कीमतों पर LPG सिलेंडर बेचने का इल्जाम लगाया गया है. उन्होंने नकली/अस्तित्वहीन कस्टमर्स के नाम पर बिक्री दिखाई, जिससे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) को धोखा मिला और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के नियमों का उल्लंघन हुआ. यह भी कहा गया कि 21 मई, 2010 को IOCL और CBI के अधिकारियों ने मिलकर सरप्राइज चेक किया, जब आरोपी फर्म के रजिस्टर, वाउचर और दूसरे रिकॉर्ड की जांच और वेरिफिकेशन किया गया. CBI ने आरोप लगाया था कि वेरिफिकेशन से पहली नज़र में पता चला कि शिवनिक्का एंटरप्राइज ऐसे कस्टमर्स के नाम पर सिलेंडर सप्लाई के लिए रिफिल वाउचर बना रही थी जो अस्तित्व में नहीं थे और उस पर इसे ब्लैक मार्केट में बेचने का शक था.

UAE ने अपने नागरिकों के ईरान, लेबनान और इराक जाने पर लगाया प्रतिबंध, सुरक्षा कारणों से लिया फैसला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय तनाव और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए एक अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने गुरुवार, 30 अप्रैल को घोषणा की कि अमीराती नागरिकों के ईरान, लेबनान और इराक जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

तुरंत स्वदेश लौटने की सलाह

मंत्रालय ने न केवल नई यात्राओं पर रोक लगाई है, बल्कि उन यूएई नागरिकों से भी तुरंत अपने देश लौटने का आग्रह किया है जो वर्तमान में इन तीन देशों में मौजूद हैं। यह निर्णय क्षेत्रीय घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी करने और विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के तहत लिया गया है।

जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर

विदेश मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि सभी नागरिक सरकार द्वारा जारी निर्देशों और आधिकारिक सलाह का सख्ती से पालन करें। सुरक्षा उपायों के हिस्से के रूप में, ईरान, लेबनान और इराक में मौजूद नागरिकों को सहायता के लिए मंत्रालय के संपर्क नंबर +97180044444 पर संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा को प्राथमिकता

यह कदम यूएई द्वारा अपने नागरिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की नीति का हिस्सा है। वर्तमान में क्षेत्र में चल रहे घटनाक्रमों के कारण नागरिकों को किसी भी संभावित जोखिम से बचाने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है,।

बंगाल चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों पर TMC और EC आमने-सामने, सुप्रीम कोर्ट कल करेगी सुनवाई

तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल चुनावों के लिए मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. एआईटीसी ने कल के कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पार्टी द्वारा राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को इन भूमिकाओं से बाहर रखने के खिलाफ दायर अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया गया था. पार्टी सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग कर रही थी, जिसको मान लिया गया है. क्योंकि मतगणना 4 मई को होनी है. तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. जस्टिस पी एस नारासिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बगची की बेंच याचिका पर कल सुनवाई करेगी. याचिका में केवल केंद्र सरकार/पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने पर आपत्ति जताई गई थी. ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा राहत से इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

हाईकोर्ट के समक्ष, एआईटीसी ने पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक मतगणना चौकी पर मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक में से कम से कम एक केंद्र सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी होना चाहिए. जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, अब ममता सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची है.

केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप

पहले चरण के मतदान से ही ममता सरकार चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा रही है. गुरुवार को स्ट्रांग रूम को लेकर भी बीजेपी और ऱ्स्ट कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ है. ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे.

1 मई विश्व मजदूर दिवस पर विशेष

मेहनतकशो के हक का त्यौहार कहानी

मई के महीने में विश्वभर प्रतिवर्ष 1 तारीख को मेहनतकशों के त्यौहार के रूपमें मनाया जाता है। यह दिवस उन श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों के सम्मान में समर्पित है, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से समाज और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। यह औपचारिक उत्सव नहीं, अपितु श्रमिकों के अधिकारों, उनके संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को स्मरण करने का सशक्त अवसर है। साथ ही, यह हमें उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के संकल्प की प्रेरणा देता है। यह हमें स्मरण कराता है कि आज जो 'आठ घंटे कार्य, आठ घंटे विश्राम और आठ घंटे मनोरंजन' का अधिकार हमें प्राप्त है, वह किसी की कृपा का फल नहीं है। दीर्घकालीन संघर्षों का प्रतिफल है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति के समय श्रमिकों का शोषण चरम पर था। उनसे 12 से 16 घंटे तक कार्य कराया जाता था, जबकि उन्हें न तो उचित वेतन मिलता था और न ही सुरक्षित कार्य-परिस्थितियां उपलब्ध थीं। इस अन्याय के विरुद्ध श्रमिकों ने संगठित होकर संघर्ष प्रारंभ किया। वर्ष 1886 में अमेरिका के शिकागो नगर में मजदूरों ने आठ घंटे के कार्यदिवस की मांग को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल की, जिसे 'हेमार्केट आंदोलन' के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन श्रमिक इतिहास का एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ है। इसने पूरे विश्व में श्रमिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलायी और अंततः आठ घंटे के कार्यदिवस की अवधारणा को मान्यता दिलायी। श्रमिक आंदोलनों के इतिहास में 1871 का 'पेरिस कम्यून' भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि श्रमिक वर्ग अपने सामूहिक साहस और संगठन के बल पर सत्ता को अपने हाथों में लेकर एक अधिक न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण व्यवस्था स्थापित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, 1917 की रूसी क्रांति तथा 1949 की चीनी क्रांति जैसे आंदोलनों ने भी यह स्पष्ट किया कि संगठित श्रमिक वर्ग सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। भारत में भी मजदूर दिवस का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। इसका प्रथम आयोजन 1923 में चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) में किया गया था, जिसकी पहल श्रमिक नेता सिंगारवेलु चेट्टियार ने की थी। तब से यह दिवस भारत में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए निरंतर मनाया जाता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी मजदूर वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

की गिरफ्तारी के विरोध में हुई हड़ताल, 1930 का शोलापुर आंदोलन तथा 1946 का नौसैनिक विद्रोह इस तथ्य के सशक्त प्रमाण हैं कि श्रमिकों ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मजदूर समाज का वह आधारभूत वर्ग है, जो अपने श्रम और समर्पण से राष्ट्र की प्रगति को गति प्रदान करता है। निर्माण कार्य, कृषि, उद्योग, परिवहन और सेवा क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान है। वे न केवल आर्थिक विकास को सुदृढ़ करते हैं, बल्कि समाज की संरचना को भी स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसके बावजूद, यह एक कटु सत्य है कि आज भी अनेक मजदूर उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आधुनिक युग में श्रमिकों की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, किंतु अनेक चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्हें स्थायी रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम और महिला श्रमिकों के साथ होने वाला भेदभाव भी समाज के समक्ष गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित है। समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, तकनीकी विकास और वैश्वीकरण ने श्रम के स्वरूप को बदल दिया है। गिग इकॉनमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अस्थायी रोजगार के नए मॉडल ने अवसरों के साथ-साथ असुरक्षाएं भी बढ़ाई हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नई और प्रभावी नीतियां बनाई जाएं, ताकि बदलते समय के साथ उनकी गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मजदूर दिवस हमें आत्ममंथन का अवसर भी प्रदान करता है। यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि क्या हम वास्तव में अपने श्रमिकों के साथ न्याय कर रहे हैं। यह केवल सरकार या उद्योगपतियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह श्रमिकों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का व्यवहार करे। शिक्षा और जागरूकता, श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के प्रमुख साधन हैं। जब श्रमिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, तब वे अपने हितों की रक्षा अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। साथ ही, कौशल विकास और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से उनके लिए बेहतर रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा सकते हैं। मई दिवस का महत्व केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है, जो हमें प्रतिदिन श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रेरित करती है। यह दिवस हमें एक ऐसे समाज की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है, जहां शोषण, असमानता और अन्याय के लिए कोई स्थान न हो, और जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। मजदूर दिवस श्रम, संघर्ष, एकता और परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसके श्रमिकों के कल्याण और सम्मान में निहित होती है। अतः हमें इस दिवस की भावना को आत्मसात करते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण, समानतापूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यही मजदूर दिवस की सच्ची सार्थकता है। (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं)

कछुए की तरह रेंग रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सपना

संपादक/लेखकः राजीव शुक्ला

[छठे वर्ष में भी चुनौतियाँ बरकरार, क्रियान्वयन की गति धीमी]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू हुए छह वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान 5+3+3+4 की नई संरचना, बहु-विषयी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और निरंतर मूल्यांकन जैसे सुधारों की दिशा में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन आधारभूत चुनौतियाँ–शिक्षक कमी, बुनियादी ढांचे की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता और धनराशि की कमी–अभी भी शिक्षा व्यवस्था को जकड़े हुए हैं। विशेषज्ञों और रिपोर्टों के अनुसार, नीति का वास्तविक रूपांतरण अभी भी दूर है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और सरकारी स्कूलों में।

NEP 2020 का मूल उद्देश्य रट्टा-आधारित शिक्षा को समाप्त कर कौशल-उन्मुख, लचीली और समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करना था। नीति में सार्वजनिक शिक्षा पर जीडीपी का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2026 तक यह आंकड़ा अभी भी लगभग 2.9-3 प्रतिशत के आसपास ही है। इससे बुनियादी ढांचा विकास, शिक्षक क्षमता निर्माण और डिजिटल विस्तार प्रभावित हो रहा है।

देशभर में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लाखों पद खाली हैं, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रिक्तियां और बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह समस्या और गंभीर है, जहां शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित हो रहा है। कई शिक्षक अनुबंधित या अपर्याप्त प्रशिक्षित हैं, जिससे NEP की नई शिक्षण पद्धतियों– अनुभव- आधारित सीखना, समस्या- समाधान का क्रियान्वयन चुनौतीपूर्ण हो गया है।

बुनियादी ढांचे की स्थिति भी चिंताजनक है। ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और स्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी डिजिटल डिवाइड को बढ़ा रही है। NEP में बहु-भाषी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया गया है, लेकिन पाठ्यपुस्तकों, प्रशिक्षित शिक्षकों और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण की चुनौती बनी हुई है। कई राज्यों में, विशेषकर दक्षिण भारत में, तीन-भाषा फॉर्मूला और कुछ प्रावधानों पर विरोध या आंशिक स्वीकार्यता देखी जा रही है।

उच्च शिक्षा में भी चुनौतियाँ समान हैं। लचीले प्रवेश-निकास विकल्प, क्रेडिट बैंक और बहु-विषयी पाठ्यक्रमों को लागू करने में संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण की कमी बाधक बन रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी और उपकरणों की उपलब्धता ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंच पा रही है।

उत्तर प्रदेश, जहां शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में बच्चे प्रभावित होते हैं, NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ोतरी दी गई है–बुनियादी शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपये (15 प्रतिशत वृद्धि) और उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस बढ़ाते हुए UP बोर्ड ने 2026-27 सत्र से कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम NEP के स्किल डेवलपमेंट लक्ष्य से मेल खाता है।

हाल ही में लखनऊ में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव 2026 में 'योगी मॉडल' ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी (FLN), अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, AI और एडटेक के उपयोग, निरंतर मूल्यांकन और शिक्षक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। राज्य सरकार स्मार्ट स्कूलों का विस्तार, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल और अभ्युदय कोचिंग जैसी पहलों पर काम कर रही है।

फिर भी, UP में भी शिक्षक रिक्तियां (लगभग 1.93 लाख से अधिक), स्कूल मर्जर की प्रक्रिया और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी चर्चा में रहती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन अभी कम है, जो दर्शाता है कि जागरूकता और बुनियादी ढांचे पर और काम की जरूरत है। NEP के छठे वर्ष में हम एक मोड़ पर खड़े हैं।

जहां नीति की दिशा सही है, वहीं क्रियान्वयन की गति और गुणवत्ता बढ़ाना अनिवार्य है। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित होगा। सरकारों, शिक्षाविदों और समाज को मिलकर इस 'शिक्षा क्रांति' को वास्तविकता बनाने की जरूरत है।

शिक्षा राष्ट्र का भविष्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को मात्र नीति-पत्र नहीं, बल्कि जन-आंदोलन बनाना होगा। बजट बढ़ोतरी और राज्य-स्तरीय पहलें सराहनीय हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव तभी दिखेगा जब हर स्कूल में योग्य शिक्षक, उचित बुनियादी ढांचा और छात्र-केंद्रित वातावरण उपलब्ध होगा। समय अब प्रतीक्षा का नहीं, त्वरित और प्रभावी कार्रवाई का है।

बाल श्रम की व्यथा और कठोर श्रम करते हाथ मूल सुविधाओं से वंचित

(1 मई, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस केवल श्रमिकों के सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य अदृश्य हाथों की पीड़ा को भी सामने लाता है जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। भारत जैसे विकासशील देश में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ श्रम के साथ-साथ बाल श्रम की समस्या भी एक गहरी सामाजिक विडंबना के रूप में उपस्थित है। संविधान और कानूनों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक उद्योगों, कारखानों, होटलों, ढाबों या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों में कार्य कराना अपराध है। इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि देश के छोटे-बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में लाखों बच्चे आज भी श्रम के बोझ तले दबे हुए हैं। वे कभी चाय की दुकानों पर काम करते दिखते हैं, कभी पटाखा उद्योगों में, तो कभी कचरा बीनते या भीख मांगते हुए। यह केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि उनके बचपन, शिक्षा और भविष्य का भी हनन है।

बाल श्रम की जड़ें गहरी हैं।

गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अशिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। कई परिवारों में आर्थिक मजबूरी इतनी तीव्र होती है कि वे स्वयं अपने बच्चों को श्रम के दलदल में धकेल देते हैं। इसके अतिरिक्त अभिभावकों की असामयिक मृत्यु, बीमारी या परिवार में अधिक सदस्यों का होना भी बच्चों को समय से पहले जिम्मेदारियों के बोझ तले ला देता है। बाल श्रमिकों का शोषण बहुआयामी होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। उन्हें वयस्क श्रमिकों की तुलना में बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है, जिससे नियोजकों के लिए वे सस्ते और सुविधाजनक श्रम का स्रोत बन जाते हैं। यही कारण है कि बाल श्रम की प्रवृत्ति समाप्त होने के बजाय कई स्थानों पर बढ़ती दिखाई देती है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कानून और योजनाएँ लागू की हैं, जैसे बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा पोषण, शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़ी अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ जैसे संगठन बाल श्रम उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन 138 और 182 विशेष रूप से बाल श्रम के उन्मूलन और खतरनाक कार्यों से बच्चों को मुक्त कराने पर केंद्रित हैं। फिर भी, समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से ही संभव है। दुर्भाग्यवश, कई बार इन कानूनों का पालन कराने वाली एजेंसियाँ भ्रष्टाचार, लापरवाही और लालफीताशाही की शिकार हो जाती हैं। परिणामस्वरूप, नियोजक आसानी से बच निकलते हैं और बच्चे शोषण की आग में झोंक दिए जाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बाल श्रम केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक प्रश्न भी है। जब तक समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं बढ़ेगी, जब तक हम बच्चों को श्रम नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कार का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी।

मजदूर वर्ग की व्यापक स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आज भी न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षित कार्यस्थल जैसे मूल अधिकारों से वंचित हैं। प्रवासी मजदूरों की स्थिति, विशेषकर महामारी के समय, ने इस सच्चाई को उजागर कर दिया कि श्रमिक वर्ग हमारे विकास का आधार होने के बावजूद सबसे अधिक उपेक्षित है।आज आवश्यकता इस बात की है कि बाल श्रम और श्रमिक शोषण के विरुद्ध एक समन्वित और सख्त नीति अपनाई जाए। इसके लिए कानूनों का कठोर और पारदर्शी क्रियान्वयन,शिक्षा और पोषण योजनाओं का प्रभावी विस्तार, गरीब परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा,और समाज में जागरूकता का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। यदि हम सचमुच एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को श्रम की बेड़ियों से मुक्त कर शिक्षा और अवसरों की मुख्यधारा में लाना होगा। अन्यथा, आज का यह बाल श्रमिक कल का कमजोर नागरिक बनेगा, और एक सुदृढ़ राष्ट्र का सपना अधूरा ही रह जाएगा।

संजीव ठाकुर

कविता

कंधों पे सपनों का भार...!

सुबह की पहली किरण संग, कंधों पे सपनों का भार,
चल पड़ता है वह चुपचाप, रचने दुनिया हर एक बार।
हाथों में मेहनत की रेखा, बहे पसीना उसकी पहचान,
ईंट-पत्थर में बसती है, उसकी हर अधूरी-सी मुस्कान।

धूप में जल रहें उसके अरमान, छांव में भी ना आराम,
रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतना-सा उसका धाम।
ऊँची-ऊँची इमारतें बोलती, उसकी खामोश हैं कहानी,
हरेक मंज़िल में गूंज रही है, उसकी मेहनत की रवानी।

ना कोई शोर, ना कोई मांग, बस काम ही उसका गीत,
दर्द को साथी बना लिया, हौसलों से रचता नव संगीत।
आओं आज ये वादा करें, सम्मान मिले हर श्रमिक को,
न सिर्फ़ शब्दों से, हृदय से कद्र करें उनकी मेहनत को।

संजय एम तराणेकर

कविता

संजीव-नी

क्योंकि आज हरिया
ने खाना नहीं खाया

क्योंकि
आज श्रमिक
हरिया ने खाना
नहीं खाया,
हथौड़े की
तेज आवाज से
भी तेज,
मस्तिष्क के तंतु कहीं
तेजी से
शून्य में विलीन हो जाते।

फिर तैरकर,
वापसी की प्रतीक्षा किए बिना,
आकर वापस बैठ जाते,
किसी अलग जगह में
जो पुरानी नहीं होती।

लेकिन हरिया
कबाड़ में हथोड़ा चलाकर
वापस आए उन विचारों का
विरोध खुलकर करना चाह रहा था,
जिसकी उसे आजादी थी,
पर इतनी ऊर्जा,ताकत और चाहत नहीं
थी।

जो बेवजह
उसकी अपनी
जिंदगी में,
अन्चाहों
की तरह,
आकर, दिमाग में चक्कर
लगाते,
हथोड़ा और जंग लगा लोहा,
आपस में जुगलबंदी कर
कोई मधुर गीत नहीं गा सकते,
कोई आशा का संकेत नहीं दे सकते।

की आने वाला कल
खुशहाली, हरीतिमा का होगा,
किसी को शायद मालूम न था
की कि हरिया ने
हथोड़ा चलाने से पहले
और बहुत पहले, और
बहुत बाद तक खाना नहीं खाया।

संजीव ठाकुर

कंकाल से उपजते व्यवस्था पर सवाल

ओडिशा के क्योंझर जिले से आई कंकाल ढोने की खबर ने देश की सामूहिक चेतना को इस कदर झकझोर दिया कि उसने आधुनिक भारत के विकास और डिजिटल साक्षरता के दावों पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। यह घटना केवल एक व्यक्ति के निजी दुख या उसकी अज्ञानता की कहानी नहीं है बल्कि यह उस अमानवीय स्थिति का जीवंत चित्रण है जहाँ एक निर्धन और असहाय नागरिक को अपनी मृत बहन के कंकाल को लेकर बैंक की दहलीज तक जाना पड़ा। 19402 रुपये की एक ऐसी राशि जो किसी संपन्न व्यक्ति के लिए बहुत मामूली हो सकती है पर एक गरीब के लिए वह उसके जीवन भर की संचित पूंजी थी। इस छोटी सी राशि को प्राप्त करने के लिए एक भाई का यह भयावह कदम समाज की संवेदनहीनता और हमारे प्रशासनिक ढांचे की चरम विफलता का एक ऐसा प्रमाण है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जब सरकारी नियम और कानून मानवीय संवेदनाओं से ऊपर हो जाते हैं तो व्यवस्था किस प्रकार एक नागरिक को अपमानित और लाचार बना देती है। बहन की मृत्यु के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी जब वह व्यक्ति अपनी छोटी सी जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दर-दर भटकता रहा तो उसकी गहरी हताशा ने उसे इस मार्ग को चुनने पर विवश कर दिया। वह व्यक्ति लगभग 3 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए उस कंकाल को कंधे पर लादकर बैंक तक पहुंचा ताकि वह वहां बैठे अधिकारियों को यह अंतिम और अकाट्य प्रमाण दे सके कि उसकी बहन अब वास्तव में इस दुनिया में नहीं है। इस दृश्य ने न केवल वहां उपस्थित लोगों को स्तब्ध कर दिया बल्कि इसने पूरे देश के प्रशासनिक और बैंकिंग तंत्र की खामियों को भी सार्वजनिक रूप से नग्न कर दिया।

इस घटना की पृष्ठभूमि में यदि हम गहराई से उतरें तो यह स्पष्ट होता है कि भारत में एक मृत्यु प्रमाण पत्र केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके बिना व्यक्ति का अस्तित्व समाप्त होने के बाद भी उसकी संपत्तियां और अधिकार एक कानूनी जाल में फंसे रहते हैं। भारत के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों के भीतर कराना अनिवार्य होता है। यह अवधि बीत जाने के बाद प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है जिसमें शपथ पत्र और विभिन्न स्तरों पर सत्यापन की आवश्यकता होती है। क्योंझर के उस आदिवासी व्यक्ति के पास न तो शिक्षा थी और न ही उसे इन जटिल कानूनी प्रक्रियाओं का कोई ज्ञान था। उसके लिए उसकी बहन की मृत्यु एक अपूरणीय क्षति थी लेकिन व्यवस्था के लिए वह केवल एक आंकड़ा भर थी जिसके लिए दस्तावेजों की पूर्ति अनिवार्य थी। जब वह व्यक्ति पहली बार बैंक गया होगा तो शायद उसे नियमों का हवाला देकर लौटा दिया गया होगा। उसके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था और न ही वह कानूनी उत्तराधिकारी होने का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर पा रहा था। यहाँ बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और पारदर्शिता के तर्क तो सही हो सकते हैं लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए था उसका वहां पूर्ण अभाव दिखा। बैंक अधिकारियों का यह कहना कि उन्होंने केवल कानूनी दस्तावेजों की मांग की थी और कभी भी मृत शरीर की उपस्थिति नहीं मांगी थी तकनीकी रूप से सही हो सकता है लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति की दृष्टि से यह उसकी असफलता और निराशा का अंत था।

यह त्रासदी तीन मुख्य स्तरों पर हुई विफलता का परिणाम है। पहला स्तर प्रशासनिक है जहाँ स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर पर उस व्यक्ति को कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। यदि स्थानीय प्रशासन ने समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र

जारी करने में उसकी सहायता की होती या उसे सही दिशा दिखाई होती तो शायद उसे इस अपमानजनक स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। दूसरा स्तर जागरूकता की कमी है जो हमारे देश के सुदूर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सरकारें भले ही डिजिटल इंडिया का नारा देती हों लेकिन धरातल पर आज भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे यह नहीं पता कि एक सामान्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर संस्थागत संवेदनशीलता का है। बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों में नियम अत्यंत कठोर होते हैं क्योंकि वहां धन की सुरक्षा का प्रश्न होता है। लेकिन क्या नियमों की इस कठोरता में मानवीय विवेक के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए? जब एक व्यक्ति बार-बार आकर अपनी विवशता बता रहा था तो क्या बैंक प्रबंधक या स्थानीय अधिकारी किसी वैकल्पिक सत्यापन की प्रक्रिया को नहीं अपना सकते थे?

इस पूरी घटना का सबसे विडंबनापूर्ण पहलू यह है कि जिस प्रशासनिक तंत्र ने उस व्यक्ति को महीनों तक चक्कर कटवाए उसी तंत्र ने इस घटना के तूल पकड़ते ही मात्र कुछ घंटों के भीतर सारे दस्तावेज तैयार कर दिए। जैसे ही यह मामला समाचारों की सुर्खियों में आया और उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो उसी दिन मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। यहाँ तक कि बैंक ने भी तुरंत 19402 रुपये की राशि संबंधित वारिसों को हस्तांतरित कर दी। यह गतिशीलता इस बात का प्रमाण है कि हमारी व्यवस्था अक्षम नहीं है बल्कि वह उदासीन है। जब तक कोई मामला राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण नहीं बनता तब तक फाइलों के पहिए नहीं घूमते। यदि यही सक्रियता दो महीने पहले दिखाई गई होती तो उस व्यक्ति को अपनी बहन के अवशेषों के साथ 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर समाज को अपनी विवशता का यह भयावह प्रदर्शन नहीं करना पड़ता।

इस मामले में कानूनी उत्तराधिकार का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानून के अनुसार उत्तराधिकार की श्रेणियां निर्धारित होती हैं और अक्सर भाई या अन्य रिश्तेदारों को प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं माना जाता जब तक कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियां न हों। यह कानूनी बारीकियां एक आम आदमी की समझ से परे होती हैं। वह व्यक्ति केवल इतना जानता था कि उसकी बहन का पैसा बैंक में है और उसे उसकी आवश्यकता है। समाज में मौजूद आर्थिक असमानता यहाँ एक और बड़ा कारक बनकर उभरती है। एक निर्धन व्यक्ति के लिए कानूनी प्रक्रिया की लागत और समय दोनों ही उसकी क्षमता से बाहर होते हैं। वह वकील नहीं कर सकता और न ही वह कचहरी के चक्कर काटने के लिए अपनी मजदूरी छोड़ सकता है। ऐसे में उसके पास केवल निराशा ही शेष रह जाती है।

यह घटना हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हमारी बैंकिंग और सरकारी प्रणालियाँ केवल साक्षर और शहरी जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं? ग्रामीण भारत की वास्तविकताएं शहरों से बिल्कुल अलग हैं। वहाँ पहचान के संकट से लेकर भाषा और प्रक्रियागत बाधाएं कदम-कदम पर खड़ी होती हैं। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं हुई और जांच के आदेश भी दिए गए लेकिन वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई बुनियादी बदलाव किए जाएंगे? केवल जांच करना या किसी कर्मचारी को निलंबित कर देना इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब हमारी व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को एक संख्या के बजाय एक इंसान के रूप में देखना शुरू करेगी।

अंत में यह कहना उचित होगा कि क्योंझर की यह घटना एक व्यक्ति की अज्ञानता से कहीं अधिक एक पूरे तंत्र की सामूहिक हार है। यह हमें यह सबक देती है कि नियम समाज की सुविधा के लिए होने चाहिए न कि समाज को प्रताड़ित करने के लिए। 19402 रुपये की उस राशि ने उस दिन केवल एक खाते का निपटारा नहीं किया बल्कि उसने हमारे आधुनिक समाज के चेहरे पर एक ऐसा दाग लगा दिया जो लंबे समय तक हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता रहेगा। विकास का अर्थ केवल ऊंची इमारतें या तेज इंटरनेट नहीं है बल्कि विकास का असली अर्थ तब है जब समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति भी सम्मान के साथ अपना अधिकार प्राप्त कर सके और उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी कंकाल का सहारा न लेना पड़े। जब तक संवेदनशीलता को प्रशासन का अनिवार्य अंग नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसी हृदयविदारक घटनाएं व्यवस्था की पोल खोलती रहेंगी और हम केवल मूकदर्शक बनकर रह जाएंगे। हमें एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जहाँ नियम मानवीय गरिमा के साथ सामंजस्य बिठा सकें ताकि कोई भी व्यक्ति स्वयं को इतना अकेला और लाचार महसूस न करे कि उसे अपनी मर्यादा और मृत अपनों के सम्मान को दांव पर लगाना पड़े।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन

नैमिषारण्य कस्बा के ठाकुर नगर तिराहा पर यशवी के मुंडन संस्कार के शुभ अवसर पर पर एक विराट कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें दूर दूर से आये कवियों ने खूब तालियां बटोरी और श्रोताओं को आनंदित किया। कवि सम्मेलन का मंच संचालन करते हुए मिश्रिख के कवि रोहित विश्वकर्मा मधुर ने पढ़ा चीर हरण में लाज बचइया कृष्ण पुकारे जाएंगे। आज भी सौवीं गाली पर सुन शीश उतारे जाएंगे। यहाँ महाभारत जब जब होगा तब पाँच पांडवो से, कौरव सौ से ज्यादा हों तब भी वो मारें जाएंगे। सिधौली के कवि डॉ देवेन्द्र कश्यप निडर ने बेटियों के महत्व को रेखांकित करते हुए पढ़ा पिताजी गर दुखी हो तो वो खाना खा नहीं सकती। बिना परिवार भाई के कहीं भी जा नहीं सकती। लगा लो फूल के पौधे भले ही आप आंगन में, मगर बेटी बिना घर में महक तो आ नहीं सकती। हरदोई के कवि अनिल अनिकेत ने पढ़ा जिन्दा रहूँगा जब तलक जीवित हूँ जहाँ में, शर्तों पे मुझे स्वर्ग भी मंजूर नहीं है। बिलग्राम के कवि हर्षित श्रीवास्तव ने पढ़ा जब तलक लक्ष्य का ज्ञान होगा नहीं। मुश्किलो का समाधान होगा नहीं। चाहे गीता , रामायण पढ़ो भागवत, मॉ दुखी है तो कल्याण होगा नहीं। संयोजक नीरज यादव 'खिचड़ी सम्राट' ने पढ़ा जो भी सच है वो लिखने को तैयार है। हम कलमकार है। हम कलमकार है। आयोजक अतुल कश्यप ने सभी कवियों का अंग वस्त्र आदि भेंट कर आभार प्रकट किया। इस दौरान निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव राजेश कश्यप, पूर्व प्रधान सुशील सक्सेना, मुकेश द्विवेदी, प्रदीप सिंह, मनोज विश्वकर्मा, दिनेश सिंह, पुष्कर सिंह यादव, अमर सिंह, मनमोहन, कामिनी कश्यप, रूबी कश्यप आदि श्रोता मौजूद रहे।

अधिवक्ताओं ने कार्य करने पर दिया जोर

मिश्रिख मिश्रिख लॉयर्स एसोसिएशन की आवश्यक बैठक अध्यक्ष बृजलाल चौधरी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फैजाबाद बार एसोसिएशन बनाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल आदि में पारित निर्देशों का सभी सदस्य अधिवक्ता पूर्णतया अनुपालन करेंगे तथा न्यायिक कार्य में पूर्ण सहयोग और प्रतिभाग करेंगे ताकि वादकारियों को समय पर न्याय सुलभ हो सके संगठन के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी मिश्रित से मिलकर कार्यकरण का प्रस्ताव दिया अधिवक्तागण सौरभ सक्सेना, नरेंद्र प्रताप जी,अकरम खान, गौरव वाजपई,ठाकुर प्रसाद, प्रेम प्रकाश राजवंशी,रजनीश कुमार, जलालुद्दीन, अमीर अहमद,सुरेंद्र मोहन, सत्यप्रकाश, अजय पांडेय, विमलेंद्र त्रिपाठी,आनंद यादव, इमरान अहमद,अभिषेक विमल, पुष्पेंद्र गुप्ता, सुनील प्रताप सिंह, आदि उपस्थित रहे।

भाजपा की जन आक्रोश रैली में उमड़ा जनसैलाब,विपक्षी नीतियों के खिलाफ भरी हुंकार

महमूदाबाद- सीतापुर आज महमूदाबाद नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जिला मंत्री कमलेश तिवारी के संरक्षण में आयोजित इस रैली के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी एकजुटता और सांगठनिक शक्ति का प्रदर्शन किया। **प्रमुख उपस्थिति एवं नेतृत्व-** रैली का नेतृत्व जिला मंत्री कमलेश तिवारी ने किया, जिनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिनमें मुख्य रूप से ?मंडल महामंत्री राजेश जायसवाल एवं विपिन वर्मा उपाध्यक्ष राजेंद्र राजपूत, श्याम नारायण त्रिपाठी, शिवपाल रावत और मंडल उपाध्यक्ष अनिल यादव, वरिष्ठ नेता संजय वर्मा प्रमुख रूप से शामिल रहे।, इस रैली की सबसे खास बात नारी शक्ति की व्यापक भागीदारी रही। भाजपा की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर रैली को सफल बनाया। इसमें मुख्य रूप से कल्पना वर्मा, किरण यादव, पूनम वर्मा, समेस्टर शर्मा, राधा देवी, किरण वर्मा, अंजलि बाजपेई, प्रीति रावत, श्रेया भार्गव और अंजलि दिवाकर जैसे चेहरों ने शिरकत की। नगर के विभिन्न मार्गो से गुजरी इस रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्षी दलों की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता के बीच विपक्षी नीतियों को लेकर भारी आक्रोश है और भाजपा आगामी समय में इसे और भी प्रखर करेगी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। रैली के समापन पर वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक और मजबूत करने का संकल्प लिया।

प्रीपेड मीटर : बैलेंस खत्म होने पर तुरंत नहीं कटेगी बिजली

● मिलेगा 'इमरजेंसी क्रेडिट'

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

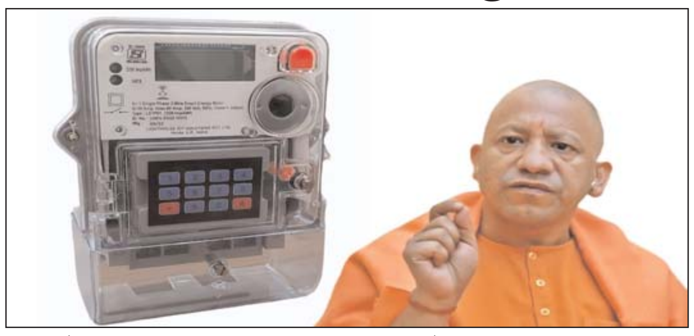

लखनऊः उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में नए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होते ही घर की बत्ती गुल नहीं होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को एक निश्चित अवधि के लिए 'इमरजेंसी क्रेडिट' की सुविधा दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बैलेंस समाप्त होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली मिलती रहेगी। वहीं 1 से 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को 3 दिन या 200 तक (जो भी बाद में हो) की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 3 दिनों का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा। इस अवधि में उपयोग की गई बिजली की लागत अगले रिचार्ज से स्वतः समायोजित कर ली जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सेवा बाधित होने का खतरा कम होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 'नो डिस्कनेक्शन पॉलिसी' भी लागू की गई है। इसके तहत शाम 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी, चाहे बैलेंस शून्य या नेगेटिव ही क्यों न हो। इसके अलावा रविवार, दूसरे शनिवार और सभी सरकारी अवकाशों के दौरान भी बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से रात और छुट्टियों में उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखकर लागू की गई है। रिचार्ज को लेकर भी प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। विभाग के अनुसार रिचार्ज सफल होने के बाद सामान्यतः 2 घंटे के भीतर बिजली स्वतः बहाल हो जाती है। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है, तो उपभोक्ता टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं, जहां स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई है। उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज की जानकारी देने के लिए एक प्रभावी SMS अलर्ट सिस्टम भी लागू किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं को चार चरणों में सूचनाएं मिलेंगी—जब बैलेंस 30 प्रतिशत रह जाएगा, जब 10 प्रतिशत बचेगा, जब बैलेंस पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और प्रत्येक माह की शुरुआत में एक मासिक अलर्ट भी भेजा जाएगा। इससे उपभोक्ता समय रहते रिचार्ज कर सकेंगे और अनावश्यक परेशानी से बच पाएंगे। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है। मोबाइल नंबर को PPCL Smart App, विभागीय वेबसाइट या 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ताकि सभी जरूरी सूचनाएं समय पर प्राप्त होती रहें। यदि किसी उपभोक्ता को यह संदेह होता है कि उनका स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है, तो वे संबंधित उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके परिसर में 'चेक मीटर' लगाया जाएगा, जिससे मीटर की सटीकता की जांच की जा सके।

इमरजेंसी क्रेडिट का नया नियम

विभागीय जानकारी के अनुसार, बैलेंस खत्म होने के बाद उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में राहत दी गई है:,1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताः बैलेंस खत्म होने के बाद भी 30 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी।,1 से 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताः इन्हें 3 दिन या ?200 (जो भी बाद में हो) तक का इमरजेंसी क्रेडिट मिलेगा।,अन्य सभी उपभोक्ताः बैलेंस शून्य होने के बाद 3 दिनों का समय दिया जाएगा।

रात और त्योहारों पर 'नो डिस्कनेक्शन' पॉलिसी

PPCL ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शाम 6:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक बिजली नहीं काटी जाएगी, भले ही बैलेंस नेगेटिव क्यों न हो। इसके अलावा रविवार, दूसरे शनिवार और सभी सार्वजनिक अवकाशों के दिन भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। हालांकि, इस अवधि के दौरान खर्च की गई बिजली की राशि अगले रिचार्ज में काट ली जाएगी।

समय पर मिलेगा SMS अलर्ट

उपभोक्ताओं को रिचार्ज की याद दिलाने के लिए सिस्टम द्वारा चार चरणों में स्स्र भेजे जाएंगेः

प्रथम अलर्टः पिछला रिचार्ज 30% बचने पर, द्वितीय अलर्ट पिछला रिचार्ज 10% बचने पर, शून्य बैलेंसः बैलेंस पूरी तरह खत्म होने पर, मासिक अलर्टः प्रत्येक माह के प्रारंभ में।

रिचार्ज और मोबाइल अपडेट की सुविधा

दस्तावेजों के अनुसार, रिचार्ज सफल होने के बाद आमतौर पर 2 घंटे के भीतर बिजली स्वतः बहाल हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, यदि किसी उपभोक्ता का मोबाइल नंबर बदल गया है, तो वे 'UPPCL Smart App' या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से उसे अपडेट कर सकते हैं।

तेज मीटर की शिकायत पर 'चेक मीटर' की सुविधा

यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि उनका स्मार्ट मीटर बहुत तेज चल रहा है, तो वे संबंधित उपखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद उनके परिसर में एक 'चेक मीटर' लगाया जाएगा ताकि मीटर की सटीकता की पुष्टि की जा सके।

निष्कर्षः इन नए दिशा-निर्देशों के लागू होने से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब न केवल बिजली कटने का डर कम होगा, बल्कि उपभोक्ता अपनी खपत, बैलेंस और खर्च को अधिक पारदर्शी और नियंत्रित तरीके से मैनेज कर सकेंगे।

बेटियों को मुफ्त लगवाए सर्वाइकल कैंसर का टीका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुरः महिलाओं में बढ़ते कैंसर के खतरों को देखते हुए सीतापुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने जनपद वासियों से अपील करते हुए 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) का टीका लगवाने का आह्वान किया है। यह पहल देश की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की गई है।

सर्वाइकल कैंसरः महिलाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा

जिलाधिकारी द्वारा जारी अपील में बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित है कि एचपीवी संक्रमण ही इस कैंसर का मुख्य कारण है। 14 से 15 वर्ष की आयु में इस टीके को लगाने से भविष्य में कैंसर की संभावना को पूर्णतः रोका जा सकता है।

मुफ्त टीकाकरण और सुरक्षा का भरोसा

बाजार में इस टीके की कीमत काफी अधिक है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के तत्वावधान में अब यह **निःशुल्क** उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है किः यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसका कोई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं है। विश्व के 100 से अधिक देशों में इसका सफल प्रयोग किया जा रहा है। अफवाहों से बचने और केवल डॉक्टरों व सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सलाह मानने का आग्रह किया गया है।

कहां लगवाएं टीका?

टीकाकरण के लिए जनपद में विशेष सत्र चलाए जा रहे हैं। पात्र किशोरियां निम्नलिखित केंद्रों पर जाकर टीका लगवा सकती हैं:

1. सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)
2. जिला महिला चिकित्सालय, सीतापुर

जरूरी दस्तावेज

टीकाकरण के लिए बेटी का जन्म प्रमाण-पत्र या आयु प्रमाणित करने वाला कोई भी सरकारी दस्तावेज साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

'स्वस्थ बेटी, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं अपील करता हूँ कि अपने परिवार और समाज की 14-15 आयु वर्ग की बेटियों को इस सुरक्षा चक्र से जरूर जोड़ें। ' डॉ. राजागणपति आर., जिलाधिकारी, सीतापुर जिला प्रशासन का लक्ष्य जनपद की शत-प्रतिशत पात्र बेटियों का टीकाकरण करना है। अधिक जानकारी के लिए नागरिक अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं।

विरोध पर महिला से मारपीट, केस दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पुरे बख्तावर मजरे हसनापुर गांव में एक महिला व उसके परिजनों से चार लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। गांव निवासिनी पीड़िता उर्मिला पत्नी सुंदर ने बताया कि पड़ोस का आशीष उसके घर की ओर मुंह करके पेशाब कर रहा था। विरोध करने पर उसने गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर आशीष और उसके परिवार की सोनी, सन्नो समेत अन्य लोग आ गए। सभी ने मिलकर उर्मिला को पीटा। बचाने आई उसकी बहन रीना व प्रीति और मां बिट्टो को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

32 लीटर अवैध कच्ची शराब व 230 किलो लहन मौके पर नष्ट, 03 अभियोग पंजीकृत

रायबरेली:- जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका के आदेशानुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध जारी प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 रोबिन आर्य एवं आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-5 सरिता सिंह मय हमराह द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों पर दबिश की कार्यवाही की गयी।टीम द्वारा महराजगंज तहसील के बछरावाँ थाना अंतर्गत संदिग्ध ग्राम - पासी टूसी, मदन टूसी एवं पश्चिम गांव तथा डलमऊ तहसील में थाना डलमऊ अंतर्गत जोहवा नटकी में अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डों/संदिग्ध घरों में दबिश के दौरान जनपद में कुल 32 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं 230 किलो लहन बरामद कर लहन को मौके पर नष्ट किया गया एवं 03 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेंगी।

02 मई को प्रदेश की सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना होगा

● उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशव्यापी संघर्ष अभियान के अंतर्गत 02 मई को धरना

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 30 अप्रैल, 2026 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशव्यापी संघर्ष अभियान के अंतर्गत दिनांक 02 मई, 2026 को प्रदेश की सभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना होगा। धरना के समापन अवसर पर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं की समस्याओं से युक्त ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा।

इसी के साथ जिला संगठन द्वारा जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा. आर.पी. मिश्र, महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा एवं जिला मंत्री महेश चंद्र ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किए जाने वाले ज्ञापन में चयन बोर्ड अधिनियम की धारा 18 एवं 21 की वापसी, पुरानी पेंशन की बहाली, वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने, 22 मार्च, 2016 की राजाज्ञा से आच्छादित शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, वंचित तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण आदि प्रमुख मांगे सम्मिलित है। जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किए जाने वाले जनपद स्तरीय ज्ञापन में विशेष कैम्प के माध्यम से शिक्षकों के अवशेषों की अनुमन्यता एवं भुगतान, एनपीएस के खातों को अपडेट किया जाना तथा एनपीएस के सेवानिवृत शिक्षकों को पेंशन एवं अन्य देयकों का भुगतान, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति आदि प्रमुख मांगे सम्मिलित हैं।

शिक्षक नेताओं ने बताया कि लखनऊ में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर मध्यान्ह 12:00 बजे से धरना होगा एवं धरना के समापन अवसर पर सायं 3:00 बजे जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसी के साथ जनपद स्तरीय समस्याओं का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक तथा वित्त एवं लेखाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

जन आक्रोश रैली में भाजपा ने महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की। रैली की शुरुआत नगर पंचायत कार्यालय परिसर से हुई। इसके बाद कार्यकर्ता वीरापासी चौक, करुणा बाजार चौराहा और मेन रोड से होते हुए आचार्य नगर मोड़ तक पहुंचे। पूरे मार्ग में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विपक्षी दलों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। नामित सभासद व भाजपा नेत्री दीपा सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष की मंशा स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। आचार्य नगर मोड़ पर सभा का आयोजन किया गया। यहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां आधी आबादी के अधिकारों का हनन कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल का विरोध कर वे महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहतीं। मंडल अध्यक्ष प्राची शालू ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को महिलाओं के लिए लाभकारी हैं। रैली के दौरान पुलिस व्यवस्था भी सतर्क रही। पूरे मार्ग पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता रवींद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष प्राची शालू, दीपा सिंह, सपना पासवान, राजेश निर्मल, रमेश सिंह, शानू बाजपेई, ब्रह्मेंद्र सिंह, महेश सोनी, अवधेश सविता, यतीन चौहान और अखिलेश बाजपेई सहित कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।

मेधावियों का महाकुंभः महमूदाबाद में गूंजा सफलता का जयघोष

●साइकिल और सोलर पैनल से नवाजे गए होनहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महमूदाबाद-सीतापुर स्व. महेन्द्र सिंह वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित'प्रतिभा सम्मान समारोह' ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की। इस भव्य आयोजन में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की प्रदेश मेरिट सूची में टॉप 10 में स्थान बनाने वाले सीतापुर के मेधावियों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा और ट्रस्ट के अध्यक्ष उत्कर्ष वर्मा ने कुल 17 छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों और गुरुजनों को सम्मानित कर उनके संघर्ष को सलाम किया। मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए स्मृतिचिन्ह, साइकिल और विशेष उपहार भेंट किए गए। इस दौरान न केवल बच्चों को, बल्कि उनकी सफलता की नींव रखने वाले माता-पिता और गुरुओं को भी माल्यार्पण एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने मेधावियों की आगे की पढ़ाई के लिए दिल खोलकर सहयोग किया, जिनमे डॉ. अनिरुद्ध वर्मा (प्रसिद्ध चिकित्सक) ने प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेज की टॉपर छात्रा को प्रोत्साहन राशि 21 हज़ार भेंट की। साथ ही, दो मेधावी छात्राओं की अगले दो वर्षों तक शिक्षा का संपूर्ण खर्च उठाने का जिम्मा लिया।

वरिष्ठ समाजसेवी अरुण कुमार वर्मा 'मुन्ना' ने भी प्रकाश ग्रुप की दो बेटियों की दो साल की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हुए प्रति माह 1100 की सहायता राशि सीधे विद्यालय पहुँचाने की घोषणा की। सत्यम वर्मा ने हाईस्कूल की प्रदेश मेरिट में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्रा को 2 किलोवाट का सोलर पैनल भेंट किया, ताकि बिजली की समस्या उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'मैं केवल एक सेवक हूँ' यह कहते हुए वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की उपलब्धि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। ट्रस्ट द्वारा किया गया यह सम्मान समारोह मात्र एक छोटा सा प्रयास है। मैं तो आप सबके बीच एक सेवक के रूप में हूँ। इस सफलता के पीछे उन गुरुओं और अभिभावकों का त्याग है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चों को टूटने नहीं दिया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष आमिर अराफ़ात, प्रकाश इंटर कॉलेज के प्रबंधक ओमप्रकाश वर्मा, शशि सिंह, कोमल वर्मा, अरुण वर्मा, जीनियस कोचिंग के प्रबंधक आनंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख मुकेश वर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में इन युवा प्रतिभाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह आयोजन न केवल एक सम्मान समारोह था, बल्कि समाज के लिए एक संदेश था कि यदि प्रतिभा को सही प्रोत्साहन मिले, तो ग्रामीण अंचल के बच्चे भी आसमान को छू सकते हैं।

डीएम की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

● सुरक्षित व सुगम यातायात के लिए दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं सुगम बनाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान राजमार्गो पर अवैध रूप से बनाए गए कटों को बंद कराने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित एवं प्रभावी पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने, पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रवर्तन कार्यवाहियों को और अधिक सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में विभिन्न विभागों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों को समय से अद्यतन करने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के प्रमुख चौराहों को यातायात की दृष्टि से अधिक सुगम एवं सुरक्षित बनाया जाए तथा सड़कों पर किए गए अतिक्रमणों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। साथ ही, चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के सुधार एवं निवारण के कार्यों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि गंगा एक्सप्रेसवे पर यातायात प्रारंभ हो चुका है, अतः वहां भी सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एक्सप्रेसवे पर किसी भी प्रकार की स्टंटबाजी अथवा अराजक गतिविधिया न हो यह सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि गुड सेमेरिटन योजना के प्रोत्साहन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) अमृता सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन उमेश चंद कटियार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गंगा में छोड़े गए 30 हजार मछली के अंगुलिका बीज

प्रयागराज। गंगा नदी में घटती मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सिफरी) प्रयागराज ने संगम तट पर 30 हजार मछलियों के अंगुलिका बीज गंगा में छोड़ा। गुरुवार को यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत आयोजित किया गया। इस रैंचिंग कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रमुख कार्प प्रजातियों कतला, रोहू और मृगल के अंगुलिका बीज गंगा नदी में प्रवाहित किए गए। वैज्ञानिकों के अनुसार एक किलोग्राम में लगभग 66 मछलियां होती हैं, इस प्रकार कुल करीब 455 किलोग्राम मछलियों को नदी में छोड़ा गया। वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. धर्म नाथ झा ने कहा कि गंगा नदी में घटती महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए नियमित रूप से बीज रैंचिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य केवल मछलियों की संख्या बढ़ाना ही नहीं बल्कि लोगों को गंगा की स्वच्छता और जैव विविधता के प्रति जागरूक करना भी है। सिफरी के केंद्राध्यक्ष डा. बीआर चव्हाण ने अपने संबोधन में गंगा नदी में मछलियों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मत्स्य संसाधन नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं।

बादाम देकर अनोखा प्रदर्शनः लो वोल्टेज और स्मार्ट मीटर बिलिंग के खिलाफ किसानों का विरोध

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां/ सीतापुर क्षेत्र में लगातार बनी लो वोल्टेज की समस्या और स्मार्ट मीटर में अधिक बिल आने से परेशान ग्रामीणों ने आज एक अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी शुभम रस्तोगी के नेतृत्व में किसानों व क्षेत्रवासियों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को बादाम भेंट कर 'याददाश्त ताजा करने' का संदेश दिया। प्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग बिसवां को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि लंबे समय से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति होने के बावजूद वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखे, मोटर और अन्य उपकरण सही से काम नहीं कर पाते। वहीं, स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में असामान्य वृद्धि की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। किसान नेता शुभम रस्तोगी का कहना है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि लो वोल्टेज की समस्या का शीघ्र स्थायी समाधान कराया जाए और स्मार्ट मीटर की बिलिंग की जांच कर सही बिलिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। इस मौके पर वीरेन्द्र वर्मा, अमर सिंह पटेल, मोहित कश्यप, फैसल खान, अफसर अंसारी, अशोक यादव, सुनील, अभिषेक आदि लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान 'बादाम देकर याद दिलाने' का यह तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा।

चोरी की बाइक के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली पुलिस टीम ने बृहस्पतिवार को बाइक चोरी के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास चोरी की हुई बाइक बरामद की। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है। मंगलवार को बछरावां रोड पर मेरुई गांव के निकट से बाइक चोरी हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर तलाश शुरू की। पुलिस ने पूरे गुरदी का पुरवा मजरे कोरिहरा गांव निवासी अंशु शर्मा वह सचिन को गिरफ्तार किया। दोनों के पास चोरी की गई बाइक बरामद हुई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को गिरफ्तार का जेल भेजा गया है।

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली के द्वारका में बड़ा हादसा, गोल्फ कोर्स के तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत

दिल्ली। दिल्ली के द्वारका गोल्फ कोर्स में तीन बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस की शुरुआती जांच में चारदीवारी कूदकर प्रवेश करने व डूबकर मरने की बात सामने आई है। बताया गया कि तीनों बच्चे गोयला के रहने वाले थे। मरने वालों में रवि जायसवाल व वीर जायसवाल दो सगे भाई थे, जबकि तीसरे मृतक का नाम हर्ष बताया गया है। डीसीपी द्वारका के अनुसार, आज सुबह करीब 7:07 बजे पीएस सेक्टर-23 द्वारका को सेक्टर 24 गोल्फ कोर्स के एक तालाब में तीन बच्चों के डूबने की सूचना एक पीसीआर से मिली। सूचना मिलते ही एसएचओ अपने स्टाफ के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके अलावा सभी एजेंसियों को भी तुरंत सूचित किया गया। वहीं, घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि लगभग 8 से 10 साल के तीन बच्चे तालाब में डूबे हुए थे। फायर ब्रिगेड की मदद से तीनों बच्चों को पानी से निकाला गया। उनके कपड़े तालाब के बाहर मिले। शक है कि बच्चे वहां नहाने गए थे और गलती से डूब गए। बच्चों की पहचान की जा रही है। अभी तक कोई गुमशुदा जानकारी नहीं मिली है।

शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया

उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके से सबूत इकट्ठा करने के लिए, फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया है। पुलिस ने कहा कि डूबने के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है। डीडीए की ओर से इस घटना की जांच के लिए डायरेक्टर के अंडर तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है और उसे एक हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जांच के आधार पर अगर जरूरी हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

'दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिल्लीवासी है', बिहार के परिवार से मिलकर बोलीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली। जाफरपुरकलां में दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने पिछले दिनों पांडव नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। उसके स्वजन विधायक पवन शर्मा के साथ बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले। मुख्यमंत्री ने युवक की हत्या पर शोक जताया और उसके स्वजनों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

दोषियों को कड़ी सजा का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री ने मृतक के स्वजनों से मुलाकात की फोटो एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'एक बेटे का असमय चले जाना माता-पिता के लिए कितना बड़ा दुख होता है, इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इस कठिन घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। दिल्ली सरकार उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।' उन्होंने कहा कि यह घटना अस्वीकार्य है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार के एक बेटे के साथ हुई इस घटना पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच में कोई लापरवाही न हो और दोषियों को कठोरतम दंड मिले। सीएम ने कहा कि देश के हर राज्य से आकर दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिल्लीवासी है। वह हमारा परिवार है। क्षेत्रीयता के आधार पर हिंसा और अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

बाहरी दिल्ली में कूड़े के ढेर से हाहाकार, बीमारियों का खतरा बढ़ा; लोग परेशान

दिल्ली। बाहरी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बने ढलावघरों के बाहर कूड़े के ढेर के कारण गंदगी फैली हुई है। सुल्तानपुरी व मंगोलपुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों के ढलावघरों के बाहर कूड़े का अंबार दिखाई दे रहा है। कई दिनों तक गंदगी के कारण आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। कूड़े से आने वाली बदबू, मच्छर व मक्खियों की भरमार हो चुकी है। जिसकी वजह से बीमारी की आशंका भी बढ़ गई है। मंगोलपुर गांव के टेंपो स्टैंड के पास बने ढलावघर के बाहर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। आसपास गंदगी से बदबू आने के कारण लोग परेशान है। कूड़े में खाना तलाशते बेसहारा गोवंशी के कारण जाम की भीषिति बनी रहती है। ढलवा घर से कुछ दूरी पर स्कूल है। स्कूल में पढ़ने वाले 500 से अधिक छात्र-छात्रा गंदगी के पास से गुजरने को मजबूर है। सुल्तानपुरी के पी-3 ब्लाक बना ढलावघर में क्षमता से अधिक कूड़ा इकट्ठा होने के कारण सड़क पर कूड़े का ढेर लग गया। गंदगी की वजह से लगभग पांच हजार से अधिक लोग प्रभावित है। यहां आसपास तीन ढलावघर हुआ करते थे। जिनमें से दो ढलावघरों को बंद कर दिया गया और सुल्तानपुरी पी-1, पी-2, पी-2 व कृष्ण विहार सहित कई ब्लाक के बीच एक ही ढलावघर रह गया। ऐसे में ढलावघर के कूड़े का सड़क तक आ जाता है। लेकिन ढलावघर से कचरा उठने वाले लोगों के बाद स्थिति गंभीर हो चुकी है। ढलावघर के आसपास के 500 से अधिक मकान है। बदबू के कारण इन घरों के लोगों का रहना ही मुश्किल हो चुका है। एक हजार से अधिक स्कूली बच्चे गंदगी के बीच से गुजरते है। तकरीबन 50 मीटर के फासले पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों कक्षा में बैठना दूभर हो चुका है।

'मां, माटी और मानुष की सरकार बना रहे हैं'

● रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता का पहला बयान, कहा- 226 सीटें जीतेंगे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मां, माटी और मानुष की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी 226 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रॉंग रूम की दिन-रात रखवाली करने के लिए भी कहा है। बता दें कि सीएम ममता ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में मुख्यमंत्री ममता ने जनता को संबोधन करते हुए आभार जताया और चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए घटनाक्रम पर गंभीर आरोप लगाए।

मतदाताओं का जताया आभार

सीएम ममता ने कहा, बंगाल के मां, माटी, मानुष को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छे से रहें हैं और स्वस्थ रहें। आप सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूं क्योंकि इतनी धूप में और इतने अत्याचार झेलकर आप लोगों ने जिस हिसाब से वोट दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मैं अपने कर्मियों का भी आभार जताती हूं जिन्होंने तमाम अत्याचार को बर्दाश्त करके, ना सिर्फ सेंट्रल फोर्स बल्कि यहां के फोर्स का भी अत्याचार सहन करके अपने काम किया।

मतगणना के दिन मेरी प्रेस वार्ता तक काउंटिंग टेबल पर रहें कार्यकर्ता'

सीएम ममता ने आगे कहा, मैं जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस न कर लूं, काउंटिंग एरिया को छोड़कर कोई न जाए। यह भी ध्यान रखना है कि ईवीएम की काउंटिंग के बाद उसका डाटा कम्प्यूटर में सही लिखा जा रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के नंबर भाजपा में जोड़ दिए जाएं।

'केंद्रीय बल भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं'

उन्होंने कहा, भारत सरकार की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री-गृह मंत्री से लेकर 19 भाजपा शासित राज्यों के नेताओं ने बंगाल के लोगों को कब्जाने की कोशिश की। मैं यह बताती हूं कि मतदाता पेटी में वोट जब्त हो गए हैं। मैं बहुत निश्चित होकर बोल रही हूं कि जो टीवी पर दिख रहा है वो सब पैसों का खेल है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रही हूं कि 2026 में हम 226 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। लोगों ने जिस तरह वोट दिया है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा ने प्रेस के जरिये ये (एग्जिट पोल) कराया है। ये लोग ईडी, सीबीआई के जरिये चमकाते हैं। ममता ने कहा कि अमित शाह के सीधे निर्देश पर पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान केंद्रीय बल भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

'2026 में तृणमूल कांग्रेस 226 सीट का आंकड़ा पार करेगी'

उन्होंने कहा, भारत सरकार की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री-गृह मंत्री से लेकर 19 बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं ने बंगाल के लोगों को कब्जाने की कोशिश की। मैं यह बताती हूं कि मतदाता पेटी में वोट जब्त हो गए हैं। मैं बहुत निश्चित होकर बोल रही हूं कि जो टीवी पर दिख रहा है वो सब पैसों का खेल है। मैं स्पष्ट रूप से बोल रही हूं कि 2026 में हम 226 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। लोगों ने जिस तरह वोट दिया है उसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। भाजपा ने प्रेस के जरिये ये (एग्जिट पोल) कराया है। ये लोग ईडी, सीबीआई के जरिये चमकाते हैं।

एग्जिट पोल को ममता ने बताया गलत

सीएम ममता ने कहा, मैं दो दिन से सो नहीं पाई हूं। भाजपा तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी लोगों से उनका अधिकार नहीं छीन पाई। यही कारण है कि उन्होंने इसके जरिये (एग्जिट पोल) अंतिम खेल खेला है जिससे हमारे कर्मियों का मनोबल टूट जाए।

अगर सच्चाई सामने आई तो शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा। शेयर मार्केट को सांत्वना देने के लिए ये किया है। यह मेरे को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है। पिछले एग्जिट पोल का हवाला देते हुए सीएम ममता ने कहा कि पहले भी 2016 और 2021 में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। उन्होंने एग्जिट पोल में बीजेपी के पक्ष में दिखाया है। यह एकतरफा दिखाया है। मैं अपने कर्मियों को बोलूंगी कि आज से ही काउंटिंग के लिए पहरा देना शुरू करें। जरूरत पड़ेगी तो मैं भी अपने इलाके में पहरा दूंगी।

'फिर बनेगी मां-माटी, मानुष की सरकार'

ममता ने कहा, एक बात और कहूंगी, सभी लोग शांत रहें और संगठित होकर रहें। दीदी के प्रति और बंगाल के लोगों के प्रति भरोसा रखें। हम अपनी मां, माटी, मानुष की सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने आगे भी सरकार बनाई थी और आगे भी हम ही सरकार बनाएंगे।

'Harry Potter मूवीज में किया काम...' बॉलीवुड में आकर फ्लॉप हुआ करियर

● युवराज सिंह की पत्नी हेजल कीच ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने 'हैरी पॉटर' फ्रैंचाइजी की तीन फिल्मों में काम किया था। उन्होंने सेट पर अपने अनुभव और भारतीय फिल्मों में अपने शुरुआती संघर्षों के बारे में भी बताया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली। क्रिकेटर युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की पत्नी हेजल कीच (Hazel Keech) ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हेजल एक टाइम पर भारत आई थीं और इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रही थीं। उन्होंने साल 2007 में तमिल फिल्म बिल्ला से डेब्यू किया था। उन्होंने बॉडीगार्ड और मैक्सीमम जैसी फिल्मों में भी काम किया जहां वो सिर्फ डांस नंबर करती ही नजर आईं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारतीय फिल्मों में अपने डेब्यू से पहले हेजर हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी में काम कर चुकी हैं। ओकट्री स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में हेजल ने हैरी पॉटर के सेट पर अपने अनुभव, अपनी भारतीय विरासत,जिस पर थोड़ा बहुत भोजपुरी का प्रभाव रहा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी समस्याओं के बारे में बात की।

हैरी पॉटर फिल्म में कर चुकी हैं काम

हेजल ने खुलासा किया कि वह तीन हैरी पॉटर फिल्मों- चैंबर ऑफ सीक्रेट्स, प्रिजनर ऑफ अजकबान और गोब्लेट ऑफ फायर का हिस्सा थीं। उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया कि वो एक्स्ट्रा पार्ट थीं लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं।

सिलापथार महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीनाथ पेगु का बिदाई सम्मान समारोह

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। धेमाजी जिले के जाने-माने कॉलेजों में से एक सिलापथार महाविद्यालय, महाविद्यालय के द्वितीय स्थाई प्रिंसिपल, डॉ. लक्ष्मीनाथ पेगु ने 17 जनवरी 2012 को कॉलेज में योगदान किया कर अपने जीवन के 14 साल 4 महीने महाविद्यालय में सेवा कर आज अनुष्ठानिक रूप में सेवानिवृत्त हुए। महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में आज महाविद्यालय के छात्र एकता सभा , शिक्षक कर्मचारी समूह की तरफ से आयोजित ओर महाविद्यालय के वाइस-प्रिंसिपल लीला नेवार के संचालन में हुए बिदाई सम्मान समारोह में जिले की विभिन्न महाविद्यालय के अध्यक्ष, सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनो, जन्मलग्न से महाविद्यालय के साथ जुड़े हुए लोगो, महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारी छात्राओं ने फूलों की गुलदस्ते, गमुचा, मानपत्र से डॉ पेगु को सम्मानित किया। उनके चाहने वालों के साथ महाविद्यालय के परिवार के सभी ने उनके कार्यकाल के दौरान कॉलेज के लिए उनकी सेवाओं की भी तारीफ की और उनके रिटायरमेंट में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। बिदाई के समय पत्रकारों को दिए उनके टिप्पणी में उन्होंने कहा15 अगस्त 1979 बृहत्तर सिलापथार इलाके के लोगों के आने वाले पोढ़ी के उच्चशिक्षा के सपने को साकार करने में कामयाब रहे। ओर उनके अनुपस्थित में महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों के प्रति आह्वान किया कि महाविद्यालय के विकास के हर कार्य मे सहयोग करे ताकि महाविद्यालय के साथ इलाके के नाम रोशन करे।वह आने वाले दिनों में समाज के लिए ओर लेखन में खुद को शामिल व्यस्त रखना पसंद करेंगे।

रोहित शर्मा: 39 की उम्र में भी कई रिकॉर्ड्स के बादशाह

● हिटमैन क्यों हैं क्रिकेट के असली G.O.A.T?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी आंकड़ों से बड़े होते हैं और कुछ खिलाड़ी खुद आंकड़ों को बदल देते हैं। रोहित शर्मा उन्हीं में से एक हैं। 39वें जन्मदिन पर हिटमैन सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक युग का नाम बन चुके हैं। उनके बल्ले ने जितने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उतने शायद उन्होंने जन्मदिन भी नहीं मनाए होंगे। यही वजह है कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का G.O.A.T यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। हिटमैन टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से तो संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में अब भी उनका जलवा बरकरार है।

छक्के लगाने में सबसे आगे

रोहित शर्मा का नाम आते ही छक्कों की बारिश याद आती है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उनके नाम टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय को मिलाकर कुल 650 छक्के हैं। यह आंकड़ा बताता है कि रोहित ने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि खेल को एंटरटेनमेंट में बदल दिया। उनके बाद क्रिस गेल (553 छक्के) जैसे दिग्गज का नाम आता है।

आईसीसी टूर्नामेंट्स के असली हीरो

बड़े मंच पर बड़ा खिलाड़ी बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन रोहित इसमें भी सबसे आगे हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा (8) शतक लगाने का रिकॉर्ड उनके नाम है। दबाव जितना बढ़ा, रोहित का प्रदर्शन उतना ही शानदार।

हर फॉर्मेट के मास्टर

रोहित शर्मा उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में बतौर कप्तान शतक जड़ा है। बतौर कप्तान तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले वह पहले भारतीय और दुनिया भर में चौथे खिलाड़ी हैं। 2023 में नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। यह दिखाता है कि टेस्ट हो, वनडे या टी20, रोहित हर जगह फिट बैठते हैं।

मैच विनर की पहचान

रोहित शर्मा एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने सभी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स, जैसे कि वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीता है। इसका मतलब साफ है, जब टीम को जीत चाहिए होती है, रोहित सामने खड़े मिलते हैं।

वनडे रिकॉर्ड्स जो यकीन से परे

वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड्स किसी सपने जैसे लगते हैं। तीन डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी, 264 रन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी और 150+ स्कोर सबसे ज्यादा (8 बार) बार रोहित के नाम ही हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वनडे में रोहित का कोई मुकाबला नहीं।

टी20 के बॉस

टी20 इंटरनेशनल में भी रोहित का दबदबा कायम है। उन्होंने पांच शतक लगाए, जो संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है। उनके नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के भी हैं। वह 100 टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी। इसके अलावा वह 35 गेंदों में शतक जड़ चुके हैं, जो कि संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज है। हालांकि, वह सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज है। उन्होंने टी20 बल्लेबाजी को एक नई परिभाषा दी है।

क्यों हैं रोहित शर्मा 'G.O.A.T'?

रोहित शर्मा सिर्फ रिकॉर्ड्स का नाम नहीं हैं, बल्कि एक स्टाइल, एक क्लास और एक एरा का नाम हैं। उन्होंने हर फॉर्मेट में खुद को साबित किया, बड़े टूर्नामेंट्स में टीम को जीत दिलाई और कप्तान के रूप में भी इतिहास रचा। यही वजह है कि वह सिर्फ एक दिग्गज नहीं, बल्कि क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं।

अरोण कुमार चंद महाविद्यालय में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर जागरूकता सभा आयोजित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: 30 अप्रैल गुरुवार को हाइकोर्ट बेंच मांग कार्यान्वयन समिति, असम के काछार जिला शाखा के आह्वान पर अरोण कुमार चंद महाविद्यालय में एक महत्वपूर्ण जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुआ, जिसमें छात्रों, अधिवक्ताओं एवं जागरूक नागरिकों की सक्रिय उपस्थिति से सभा अत्यंत प्रभावशाली एवं जीवंत रही। सभा में महाविद्यालय के प्राचार्य अबू ताहेर तालुकदार, शिलचर शाखा के उपाध्यक्ष डॉ. विभाष देव, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देवनाथ, अधिवक्ता दीपक कुमार देव, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसेनजित कुमार देव, समिति के उपाध्यक्ष अधिवक्ता शांतनु नायक, संयुक्त सचिव अधिवक्ता देवोमिता चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता ज्योतिर्मय नाथ एवं अधिवक्ता धर्मानंद देव उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य प्रस्तुतकर्ता अधिवक्ता धर्मानंद देव ने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से बराक घाटी में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की आवश्यकता, न्याय प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों एवं भौगोलिक दूरी के कारण उत्पन्न समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने आंकड़ों एवं वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया। अधिवक्ता शांतनु नायक ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्देशों का उल्लेख करते हुए इस मांग की संवैधानिक एवं कानूनी महत्ता को रेखांकित किया। वहीं सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देवनाथ ने अपने अनुभवों के आधार पर न्याय प्रणाली में देरी और आम जनता की समस्याओं पर गंभीर विचार व्यक्त किए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रसेनजित कुमार देव एवं अधिवक्ता दीपक कुमार देव ने भी स्थायी हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता को न्यायसंगत एवं जनहित में आवश्यक बताया।

कार्यक्रम का संचालन अरोण कुमार चंद विधि महाविद्यालय के छात्र स्नेहांशु भट्टाचार्य ने कुशलतापूर्वक किया। सभा में लगभग सौ से अधिक छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही, जिनकी सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को और भी सफल एवं सार्थक बनाया। अंत में सभी वक्ताओं एवं उपस्थित जनों ने बराक घाटी में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को जोरदार समर्थन किया और इसे क्षेत्र के न्यायिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक बताया।

'नागरिकों का सम्मान करें', नाबालिग की प्रेग्नेंसी पर केंद्र की याचिका देख भड़का सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

भारत के उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। मामला एक 15 साल की रेप पीड़िता की 31 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार केवल पीड़िता और उसके परिवार को है, न कि सरकार को। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा दायर की गई 'क्यूरेटिव पिटीशन' (उपचारात्मक याचिका) पर कड़ा ऐतराज जताया। सरकार ने कोर्ट के उस पिछले आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दी गई थी।

कोर्ट की टिप्पणी: चीफ जस्टिस ने सरकार की ओर से पेश वकील को टोकते हुए कहा, 'नागरिकों का सम्मान करें, मैडम... आपको इसे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ पीड़िता या उसके परिवार के पास है।' 'पीड़ा का अहसास: बेंच ने भावुक होते हुए कहा कि नाबालिग ने जिस सदमे और मानसिक यंत्रणा को सहा है, उसकी भरपाई दुनिया की कोई भी चीज नहीं कर सकती।

बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर!, सड़कें बनीं नदियां, जारी हुई अलर्ट

बेंगलुरु में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने शहर में भारी तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण दीवार गिरने और करंट लगने जैसी घटनाओं में अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। भारी बारिश के चलते विधान सौध जैसी महत्वपूर्ण इमारतों और रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जबकि दर्जनों स्थानों पर पेड़ उखड़ने से यातायात और बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शहर के बुनियादी ढांचे और ड्रेनेज सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया है।

पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर असम पुलिस का कड़ा विरोध, 'जालसाजी' की जांच के लिए मांगी हिरासत

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी बहस हुई। असम पुलिस ने खेड़ा की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए उन पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पासपोर्ट के साथ 'छेड़छाड़ और जालसाजी' करने का गंभीर आरोप लगाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने जो किया वह एक गैर-जमानती अपराध है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने दस्तावेजों में जालसाजी कैसे की।

श्रीभूमि जिले के फाकोआ गांव के छात्रों की शानदार सफलता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम श्रीभूमि जिले के रामकृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फाकोआ गांव में हाल ही में घोषित असम उच्च माध्यमिक (HS) परीक्षा परिणामों के बाद खुशी और गर्व का माहौल छा गया है क्षेत्र में। गांव के छात्रों ने इस वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक क्षेत्र के प्रतिनिधि नृपेन्द्र दास ने स्वयं छात्रों के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया। यह पहली बार है जब शैनबिल क्षेत्र में इस प्रकार का व्यक्तिगत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसे स्थानीय लोग एक ऐतिहासिक पहल मान रहे हैं। नृपेन्द्र दास ने कहा, 'यह सफलता केवल छात्रों की नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। मेहनत और लगन से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी बड़े मुकाम हासिल कर सकते है।' इस वर्ष की परीक्षा में बिथिका दास (92%), मामन दास (91%) और टुसु दास (90%) ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। वहीं सानी दास ने 76% अंक हासिल कर सराहनीय प्रदर्शन किया। विद्यालय का कुल परिणाम भी उत्कृष्ट रहा, जिसमें 86% पास प्रतिशत दर्ज किया गया। शिक्षा संस्थान के अनुसार, इस वर्ष 32 छात्र प्रथम श्रेणी, 29 द्वितीय श्रेणी और 14 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसके अलावा 4 छात्रों ने डिस्टिंक्शन तथा 13 छात्रों ने स्टार मार्क्स प्राप्त किए।विद्यालय के प्रधानाचार्य मोइनुद्दीन, शिक्षक विजय दास सहित सभी शिक्षकों और प्रबंधन समिति के प्रयासों की भी सराहना की गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में छात्रों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि यह सफलता भविष्य में और बेहतर परिणामों की नींव रखेगी और फाकोआ गांव शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता रहेगा।

महुआडांड़ में दर्दनाक हादसा: स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा

● 12 वर्षीय छात्र की मौत, कई गंभीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लातेहार, झारखंड:- लातेहार जिले के महुआडांड़ प्रखंड में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 12 वर्षीय छात्र अंकुर मिंज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। मृतक अंकुर मिंज, एलेसियुस मिंज का पुत्र था और ग्राम अकसी का रहने वाला था। वह संत मिखाईल स्कूल, साले में कक्षा सात का छात्र था। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महुआडांड़ पहुंचाया। घायलों में आरसु मिंज, गोरीतिका केरकेट्टा, अनुज उरांव, रेशमा केरकेट्टा, सलमा बेक, अंशु मिंज, तुन एक्का, आस्था तिर्की, दीपासी केरकेट्टा, सोनू एक्का, अवेश कुजूर, शुभम खलखो सहित अन्य शामिल हैं। इनमें से अनुरूप एक्का, अनुज कुमार, कौतिक बाड़ा, साक्षी कुमारी और नेहा कुमारी को गंभीर स्थिति में बाहर रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज डॉ. अमीत खलखो और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी शिवपूजन बहेलिया और थाना प्रभारी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। हादसे के बाद ऑटो चालक दीपक और वाहन मालिक प्रतीम उरांव फरार हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था, जिससे यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड प्रमुख कंचन कुजूर, अजीत पाल कुजूर और जेएमएम नेता परवेज आलम समेत कई जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिले के सदर अस्पताल की बजाय गुमला रेफर किए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने महुआडांड़ और लातेहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।